

मनोहर लाल शर्मा

बनाम

नरेंद्र दामोदरदास मोदी और अन्य

(लिखित याचिका (सीआरएल) संख्या 225/2018)

14 दिसंबर, 2018

[रंजन गोगोई, सीजेआई, संजय किशन कौल और के. एम. जोसेफ, जे.]

भारत का संविधान:अनुच्छेद 32-जनहित याचिका-रक्षा मंत्रालय द्वारा फ्रांस से भारतीय वायुसेना के लिए 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद से संबंधित मुद्दा-एफआईआर दर्ज करने की मांग करने वाली याचिकाएं, राफेल सौदे में भ्रष्टाचार के आरोपों की अनुसंधान की अदालत की निगरानी और राफेल विमानों की खरीद के लिए 2016 के अंतर-सरकारी समझौते को रद्द करना-अभिनिर्धारित:निर्णय लेने की प्रक्रिया, मूल्य निर्धारण में अंतर और भारतीय ऑफसेट भागीदार-आईओपी के चयन के संबंध में भारत सरकार द्वारा रक्षा विमानों की खरीद के संवेदनशील मुद्दे पर हस्तक्षेप-ऐसे मामलों में, व्यक्तियों की धारणा इस न्यायालय द्वारा की जाने वाली जांच का आधार नहीं हो सकती है-न्यायालय अधिग्रहण की प्रक्रिया के प्रत्येक पहलू की जांच करने के लिए एक अपीलीय प्राधिकरण के रूप में नहीं बैठ सकता है-निर्णय लेने की प्रक्रिया पर संदेह नहीं किया जा सकता है-मामूली विचलन होने पर भी, अनुबंध को रद्द करने या विस्तृत जांच की आवश्यकता नहीं होगी-अदालत मूल्य निर्धारण विवरण की तुलना नहीं करेगी-उक्त सामग्री को गोपनीय क्षेत्र में रखा जाना है-रक्षा खरीद प्रक्रिया 2013 में, सरकार की भूमिका नहीं है-इस प्रकार केवल प्रेस साक्षात्कार या सुझाव न्यायिक समीक्षा का आधार नहीं बन सकते, खासकर जब दोनो पक्षों द्वारा स्पष्ट इनकार किया गया

हो-साथ ही, यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि सरकार द्वारा किसी भी पार्टी के लिए व्यावसायिक पक्षपात का मामला है।

न्यायिक समीक्षा: रक्षा से संबंधित सरकारी निर्णय विमानों की खरीद-न्यायिक समीक्षा की अनुमति-अनुबंधों, खरीद आदि के मामलों में अनुमेय न्यायिक समीक्षा की सीमा अनुबंध की विषय वस्तु के अनुसार भिन्न होती है और कोई समान मानक नहीं हो सकता है-रक्षा खरीद के अनुबंध एक अलग डिग्री और न्यायिक समीक्षा की गहराई के अधीन होने चाहिए-चुनौतियों की जांच करनी होगी।

राष्ट्रीय सुरक्षा की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, खरीद का विषय राष्ट्र की संप्रभुता के लिए महत्वपूर्ण है।

रिट याचिकाओं को खारिज करते हुए, अदालत ने अभिनिर्धारित किया-

1.1 बाहरी आक्रमण को हतोत्साहित करने और उसका सामना करने और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करने के लिए पर्याप्त सैन्य शक्ति और क्षमता, निस्संदेह, राष्ट्र के लिए अत्यधिक चिंता का विषय है। इसलिए, पर्याप्त प्रौद्योगिकी और सामग्री समर्थन के साथ रक्षा बलों का सशक्तिकरण महत्वपूर्ण है। शुरुआत में, रक्षा खरीद से संबंधित सरकारी निर्णयों की न्यायिक जांच के मानदंडों को निर्धारित करना और यह इंगित करना उचित होगा कि क्या ऐसे मानदंड निविदाओं और अनुबंधों के पुरस्कार की न्यायिक जांच के न्यायशास्त्र की तुलना में अधिक संकुचित हैं, जो आज तक सामने आया है, वैध रूप से अनुमति देगा। जारी की गई निविदा सड़कों, पुलों आदि के निर्माण के लिए नहीं है। यह विमानों की खरीद के लिए एक रक्षा निविदा है। खरीद की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, जांच का पैमाना सरकार को कहीं अधिक छूट देगा।

1.2 अनुबंधों, खरीद आदि के मामलों में अनुमेय न्यायिक समीक्षा की सीमा अनुबंध के विषय के अनुसार अलग-अलग होगी और न्यायिक समीक्षा का कोई समान मानक या गहराई नहीं हो सकती है जिसे कार्य के अधिनिर्णय या वस्तुओं/सामग्री की खरीद के सभी मामलों में लागू होने के लिए बोर्ड सिद्धांत के रूप में समझा जा सके। इस प्रकार, चुनौतियों की जांच राष्ट्रीय सुरक्षा की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए, क्योंकि खरीद का विषय राष्ट्र की संप्रभुता के लिए महत्वपूर्ण है।

जगदीश मंडल बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य। (2007) 14 एससीसी 517; मां बिंदा एक्सप्रेस वाहक और अन्य बनाम उत्तर-पूर्व सीमांत रेलवे और अन्य (2014) 3 एससीसी 760:[2013] 12 एससीआर 529; टाटा सेल्युलर बनाम भारत संघ (1994) 6 एससीसी 651:[1994] 2 पूरक एस. सी. आर. 122; सीमेंस पब्लिक कम्युनिकेशन नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम संघ भारत और अन्य (2008) 16 एससीसी 215:[2008] 15 एससीआर 585; रिलायंस एयरपोर्ट डेवलपर्स (पी) लिमिटेड बनाम हवाई अड्डे भारतीय प्राधिकरण और अन्य (2006) 10 एस. सी. सी 1:[2006] 8 पूरक एस. सी. आर. 398-संदर्भित।

2. प्रक्रिया पर वास्तव में संदेह करने का कोई अवसर नहीं है, और भले ही मामूली विचलन हुए हों, लेकिन इसके परिणामस्वरूप अनुबंध को रद्द नहीं किया जाएगा या न्यायालय द्वारा विस्तृत जांच की आवश्यकता नहीं होगी। संयुक्त अभ्यास हुए हैं और इससे राष्ट्र को वित्तीय लाभ हुआ है। यह ध्यान नहीं दिया जा सकता है कि ये रक्षा खरीद के अनुबंध हैं जो एक अलग डिग्री और न्यायिक समीक्षा की गहराई के अधीन होने चाहिए। मोटे तौर पर, प्रक्रियाओं का पालन किया गया है। विमानों की आवश्यकता पर कोई संदेह नहीं है। विमान की गुणवत्ता पर कोई सवाल नहीं है। यह भी एक तथ्य है कि 126 एमएमआरसीए की खरीद के लिए लंबी बातचीत का कोई परिणाम नहीं निकला है, और केवल यह अनुमान लगाना कि प्रारंभिक आरएफपी के

परिणामस्वरूप अनुबंध हो सकता था, कोई फायदा नहीं है। कठिन तथ्य यह है कि न केवल अनुबंध सामने नहीं आ रहा था, बल्कि बातचीत व्यावहारिक रूप से समाप्त हो गई थी, जिसके परिणामस्वरूप आर एफपी को वापस ले लिया गया था। न्यायालय 126 के स्थान पर 36 विमानों की खरीद के निर्णय के विवेक पर निर्णय नहीं दे सकता है। सरकार को 126 विमानों की खरीद के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। यह इस तथ्य के बावजूद है कि आरएफपी की वापसी से पहले ही अप्रैल 2015 में केवल 36 विमानों के लिए जाने के निर्णय की घोषणा की गई थी। देश ऐसी स्थिति में अप्रस्तुत/कम तैयार होने का जोखिम नहीं उठा सकता है जब कहा जाता है कि विरोधियों ने न केवल चौथी पीढ़ी, बल्कि पांचवीं पीढ़ी के विमान भी हासिल कर लिए हैं, जिनमें से कोई भी नहीं है। न्यायालय के लिए अधिग्रहण की प्रक्रिया के प्रत्येक पहलू की जांच करने के लिए एक अपीलीय प्राधिकरण के रूप में बैठना सही नहीं होगा।

2.2 36 राफेल लड़ाकू जेट विमानों के लिए यह प्रक्रिया 23 सितंबर, 2016 को पूरी की गई थी। तब कुछ भी सवाल नहीं उठाया गया था। यह केवल फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति के बयान का लाभ उठा रहा है, कि याचिकाओं के ये सेट दायर किए गए हैं, न केवल उस पहलू के लिए जो बयान का गठन करता है, यानी आईओपी का मुद्दा, बल्कि पूरी निर्णय लेने की प्रक्रिया और मूल्य निर्धारण के संबंध में भी।

3.1 इस न्यायालय के समक्ष रखी गई सामग्री से पता चलता है कि सरकार ने विमान की मूल कीमत के अलावा, यहां तक कि संसद को भी, इस आधार पर मूल्य निर्धारण विवरण का खुलासा नहीं किया कि मूल्य निर्धारण विवरण की संवेदनशीलता राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच समझौते का उल्लंघन करना। हालांकि, मूल्य निर्धारण का विवरण नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के साथ साझा किया गया है और सीएजी की रिपोर्ट की लोक लेखा समिति द्वारा जांच की गई है, रिपोर्ट का केवल एक संशोधित हिस्सा संसद के समक्ष रखा गया था, और

यह सार्वजनिक क्षेत्र में है। कहा जाता है कि वायु सेना प्रमुख ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले हथियारों सहित मूल्य विवरण के प्रकटीकरण के संबंध में अपनी आपत्ति व्यक्त की है। राफेल विमानों की खरीद पर भारत सरकार और फ्रांस सरकार के बीच आईजीए के अनुच्छेद 10 के तहत मूल्य निर्धारण का विवरण शामिल किया गया है, जिसमें कहा गया है कि आईजीए के तहत वर्गीकृत जानकारी और आदान-प्रदान की गई सामग्री की सुरक्षा दोनों सरकारों के बीच 25 जनवरी, 2008 को हस्ताक्षरित सुरक्षा समझौते के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होगी। इस अनिच्छा के बावजूद, अपनी अंतरात्मा को संतुष्ट करने के लिए सामग्री को अभी भी न्यायालय के समक्ष रखा गया है।

3.2 मूल आरएफपी के साथ-साथ आईजीए के तहत मूल्य विवरण और मूल विमान की कीमतों की तुलना के साथ-साथ वृद्धि लागत और वस्तु के अनुसार लागत पर व्याख्यात्मक नोट की जांच की गई है। मूल्य विवरण के अनुसार, आधिकारिक प्रत्यर्थीगणों का दावा है कि 36 राफेल विमानों की खरीद में वाणिज्यिक लाभ है। आधिकारिक प्रत्यर्थीगणों ने दावा किया है कि रखरखाव और हथियार पैकेज के लिए आईजीए में कुछ बेहतर शर्तें हैं। यह निश्चित रूप से इस न्यायालय का काम नहीं है कि वह वर्तमान जैसे मामलों में मूल्य विवरण की तुलना करे। इससे अधिक कुछ नहीं कहा गया है क्योंकि सामग्री को गोपनीय क्षेत्र में रखा जाना है।

4.1 कंपनी, रिलायंस, हाल ही में अस्तित्व में आई है, लेकिन प्रेस विज्ञप्ति से पता चलता है कि संभवतः मूल कंपनी और डसॉल्ट के बीच वर्ष 2012 से एक समझौता शुरू हुई थी। दोनों निगमों के बीच क्या बातचीत हुई, यह उनके लिए सबसे अच्छा मामला होगा, क्योंकि यह उनके वाणिज्यिक हितों का मामला है, जैसा कि वे समझते हैं। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति द्वारा दिए गए साक्षात्कार के बारे में हर तरफ से स्पष्ट इनकार किया गया है, जिसमें कहा गया है कि यह भारत सरकार है जिसने इस

मामले में फ्रांस सरकार को कोई विकल्प नहीं दिया था। उपलब्ध सामग्रियों के आधार पर यह आईओपी से संबंधित डीपीपी 2013 के खंड के विपरीत प्रतीत होता है। इस प्रकार, वाणिज्यिक व्यवस्था, इस स्तर पर, आईओपी की भागीदारी के संबंध में भारत सरकार को कोई भूमिका नहीं सौंपती है। ऐसा लगता है कि इस तरह का मामला डसॉल्ट के व्यावसायिक निर्णय पर छोड़ दिया गया है। यही कारण है कि यह कहा गया है कि भारत सरकार की भूमिका तभी शुरू होगी जब विक्रेता/आईएम निर्धारित तरीके से एक औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा, जिसमें आईओपी और ऑफसेट निर्वहन के लिए उत्पादों का विवरण होगा। जहाँ तक एचएएल की भूमिका का संबंध है, 36 विमानों की खरीद में कोई विशिष्ट भूमिका की परिकल्पना नहीं की गई है। वास्तव में, सरकार का सुझाव ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ संविदात्मक समस्याएं थीं और डसॉल्ट एचएएल द्वारा संविदात्मक दायित्व को पूरा करने के बारे में सतर्क था, जिसे पहले के अनुबंध के गैर-समापन के लिए भी जिम्मेदार कहा जाता है।

4.2 यह न तो उचित है और न ही इस न्यायालय के अनुभव के भीतर इस क्षेत्र में कदम रखना जो तकनीकी रूप से संभव है या नहीं। मुद्दा यह है कि डीपीपी 2013 में यह परिकल्पना की गई है कि विक्रेता/आईएम अपने स्वयं के आईओपी का चयन करेगा। इस प्रक्रिया में, सरकार की भूमिका की परिकल्पना नहीं की गई है और इस प्रकार, केवल प्रेस साक्षात्कार या सुझाव इस न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा का आधार नहीं बन सकते हैं, विशेष रूप से जब दोनों पक्षों द्वारा प्रेस में दिए गए बयानों का स्पष्ट खंडन किया जाता है। अभिलेख पर यह दिखाने के लिए कोई ठोस सामग्री नहीं है कि यह भारत सरकार द्वारा किसी भी पक्ष के लिए व्यावसायिक पक्षपात का मामला है, क्योंकि आईओपी चुनने का विकल्प भारत सरकार के पास नहीं है।

5. भारत सरकार द्वारा 36 रक्षा विमानों की खरीद के संवेदनशील मुद्दे पर इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं है। व्यक्तियों की धारणा

विशेष रूप से ऐसे मामलों में इस न्यायालय द्वारा मछली पकड़ने और घूमने की जांच का आधार नहीं हो सकती है। यह स्पष्ट किया जाता है कि विचार मुख्य रूप से संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के दृष्टिकोण से हैं, जिसे मामलों के तत्काल समूह में लागू किया गया है।

#### मामला कानून संदर्भ

|                               |               |         |
|-------------------------------|---------------|---------|
| (2007) 14 एस. सी. सी. 517     | संदर्भित किया | पैरा 7  |
| [2013] 12 एससीआर 529          | संदर्भित किया | पैरा 7  |
| [1994] 2 पूरक एस. सी. आर. 122 | संदर्भित किया | पैरा 8  |
| [2008] 15 एस. सी. आर. 585     | संदर्भित किया | पैरा 9  |
| [2006] 8 पूरक एस. सी. आर. 398 | संदर्भित किया | पैरा 10 |

सिविल/आपराधिक मूल न्यायनिर्णय: रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 225/2018

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत

के साथ

डब्ल्यू. पी. (सी) सं. 1205/2018, डब्ल्यू. पी. (सीआरएल.) संख्या 297, 298/2018

के. के. वेणुगोपाल, ए. जी., तुषार मेहता, एस. जी., संजय आर. हेगड़े, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री सुमन, सुश्री राज रानी ढांडा, विनीत ढांडा, एन. ए. उस्मानी, डॉ. जे. पी. ढांडा, धीरज कुमार सिंह, मृणाल कुमार, निहाल अहमद, आलोक शुक्ला, आर.

बालासुब्रमण्यम, सुश्री श्रद्धा देशमुख, ए. के. शर्मा, अधिवक्ताओं के लिए गोपी चंद उपस्थित दलों के लिए।

मनोहर लाल शर्मा, व्यक्तिगत रूप से याचिकाकर्ता।

प्रशांत भूषण, व्यक्तिगत रूप से याचिकाकर्ता।

अरुण शौरी, व्यक्तिगत रूप से याचिकाकर्ता।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

रंजन गोगोई, सीजेआई

1. जनहित याचिकाओं के रूप में दायर रिट याचिकाओं के इस समूह में उत्पन्न होने वाले मुद्दे भारतीय वायु सेना के लिए 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद से संबंधित हैं। विचाराधीन खरीद, जिसे चुनौती देने की कोशिश की गई है, की उत्पत्ति कारगिल के बाद के अनुभव में हुई है, जिसमें देश के सशस्त्र बलों की रणनीतिक जरूरतों को आगे बढ़ाने का एक नया प्रयास देखा गया।

2. वर्ष 2001 के जून महीने में, भारतीय वायु सेना की ताकत बढ़ाने के लिए 126 लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी। साथ ही, वर्ष 2002 में पहली बार एक अधिक पारदर्शी रक्षा खरीद प्रक्रिया ("डीपीपी") तैयार की गई थी। एक मजबूत 'ऑफसेट खंड' शामिल किया गया था वर्ष 2005 में डी. पी. पी. में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए और उस प्रभाव के लिए जून 2006 में सेवा गुणात्मक आवश्यकताएं ("एसक्यूआर") तैयार की गईं। 29 जून 2007 को रक्षा अधिग्रहण परिषद ("डीएसी") ने 126 मध्यम बहु-भूमिका वाले लड़ाकू विमानों (संक्षिप्त में "एम. एम. आर. सी. ए.") की खरीद के लिए "आवश्यकता की स्वीकृति" प्रदान की, जिसमें 18 सीधे उड़ान भरने वाले विमान (एकल स्कवाड्रन के बराबर) शामिल हैं, जिन्हें मूल उपकरण निर्माता ("ओईएम") से खरीदा जाना है और शेष 108 विमानों को



लाइसेंस के तहत हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (संक्षिप्त में "एचएएल") द्वारा निर्मित किया जाना है, जिन्हें हस्ताक्षर की तारीख से 11 साल की अवधि में वितरित किया जाना है। बोली प्रक्रिया अगस्त 2007 में शुरू हुई थी। अप्रैल, 2008 में छह (06) विक्रेताओं ने प्रस्ताव प्रस्तुत किए। प्रस्तावों के बाद तकनीकी और क्षेत्रीय मूल्यांकन किया गया; एक कर्मचारी मूल्यांकन रिपोर्ट और एक तकनीकी निगरानी समिति की रिपोर्ट। ये सभी कार्य वर्ष 2011 में पूरे किए गए थे। वाणिज्यिक बोलियां नवंबर, 2011 में खोली गईं और मेसर्स डसॉल्ट एविएशन (इसके बाद "डसॉल्ट" के रूप में संदर्भित) को जनवरी 2012 में एल-आई के रूप में रखा गया था। इसके बाद बातचीत शुरू हुई और जारी रही लेकिन कोई अंतिम परिणाम नहीं निकला। इस बीच, वर्ष 2014 के मध्य में केंद्र में राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव आया।

3. आधिकारिक प्रत्यर्थीगणों के अनुसार बातचीत जारी रही। 126 एमएमआरसीए के संबंध में प्रस्ताव के अनुरोध को वापस लेने की प्रक्रिया मार्च 2015 में शुरू की गई थी। 10 अप्रैल, 2015 को एक अंतर-सरकारी समझौते (जिसे इसके बाद "आईजीए" के रूप में संदर्भित किया गया है) के माध्यम से उड़ान भरने की स्थिति में 36 राफेल विमानों के अधिग्रहण के लिए एक भारत-फ्रांसीसी संयुक्त बयान जारी किया गया था और इसे डी एसी द्वारा विधिवत मंजूरी दी गई थी। 126 एमएमआरसीए के प्रस्ताव के लिए अनुरोध अंततः जून 2015 में वापस ले लिया गया था। बातचीत की गई और सुरक्षा पर मंत्रिमंडल समिति (संक्षेप में "सीसीएस") की मंजूरी के साथ अंतर-मंत्रालयी परामर्श के बाद प्रक्रिया पूरी की गई। 23 सितंबर, 2016 को 36 राफेल विमानों के संबंध में विमान पैकेज आपूर्ति प्रोटोकॉल; हथियार पैकेज आपूर्ति प्रोटोकॉल; तकनीकी व्यवस्था और ऑफसेट अनुबंधों के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। विमानों को अक्टूबर 2019 से चरणबद्ध तरीके से वितरित किया जाना था।

4. सितंबर, 2018 के महीने में कुछ समय तक स्थिति शांत रही जब कुछ समाचार पत्रों ने एक बयान की खबर दी जिसमें दावा किया गया कि फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद ने इस आशय का बयान दिया था कि फ्रांसीसी सरकार के पास भारतीय ऑफसेट भागीदारों के चयन के मामले में कोई विकल्प नहीं बचा था और भारत सरकार द्वारा रिलायंस समूह का नाम सुझाया गया था। ऐसा लगता है कि विचाराधीन रिट याचिकाओं के कारण ऐसा हुआ है।

पहली रिट याचिका अर्थात् लिखित याचिका (आपराधिक) सं.225/2018 इस न्यायालय के एक अभ्यासरत वकील श्री मनोहर लाल शर्मा द्वारा दायर की गई है। उक्त रिट याचिका में भारतीय दंड संहिता, 1860 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत अनुसंधान दर्ज करने और अदालत की निगरानी में जांच करने की मांग की गई है। 36 राफल विमानों की खरीद के लिए 2016 के अंतर-सरकारी समझौते को रद्द करने से और राहत मिलने की भी प्रार्थना की गई है।

रिट याचिका (सिविल) सं.1205/2018 श्री विनीत ढांडा द्वारा दायर की गई है, जो एक सार्वजनिक उत्साही भारतीय होने का दावा करता है। याचिकाकर्ता का कहना है कि वह समाचार पत्र के लेखों/रिपोर्टों के आधार पर इस मामले पर उत्तेजित होकर रिट याचिका दायर करने के लिए प्रेरित हुए थे।

रिट याचिका (आपराधिक) सं.297/2018 वाली तीसरी रिट याचिका एक सांसद श्री संजय सिंह द्वारा खरीद प्रक्रिया में अवैधता और गैर-पारदर्शिता का आरोप लगाते हुए दायर की गई है। उक्त रिट याचिका में "पहले के सौदे को रद्द करने" के कारणों की अनुसंधान करने की मांग की गई है और मूल्य निर्धारण में बदलाव और सबसे बढ़कर, कैसे एक 'नौसिखिया' कंपनी यानी रिलायंस डिफेंस एचएएल को ऑफसेट भागीदार के रूप में बदलने के लिए आई, इसकी अदालत से अनुसंधान करने की मांग

की गई है। अंतर-सरकारी समझौते को रद्द करने और प्राथमिकी दर्ज करने के लिए भी अनुरोध किया गया है।

श्री यशवंत सिन्हा, श्री अरुण शौरी और श्री प्रशांत भूषण ने 2018 की रिट याचिका (आपराधिक) सं.वाली चौथी और अंतिम रिट याचिका दायर की है, जिसमें सार्वजनिक भावना वाले भारतीय होने का दावा किया गया है।वे 4 अक्टूबर, 2018 को उनके द्वारा की गई एक शिकायत के अनुसार सीबीआई द्वारा एफआईआर दर्ज न किए जाने से व्यथित हैं, जो याचिकाकर्ताओं के अनुसार, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत एक संज्ञेय अपराध के होने के प्रथम दृष्टया साक्ष्य का खुलासा करती है। प्रार्थना, अन्य बातों के साथ-साथ, एक एफआईआर दर्ज करने और उसी की अनुसंधान करने और अदालत को आवधिक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश के लिए है।

5. बाहरी आक्रमण को हतोत्साहित करने और उसका सामना करने और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करने के लिए पर्याप्त सैन्य शक्ति और क्षमता, निस्संदेह, राष्ट्र के लिए अत्यधिक चिंता का विषय है।इसलिए, पर्याप्त प्रौद्योगिकी और सामग्री समर्थन के साथ रक्षा बलों का सशक्तिकरण महत्वपूर्ण है।

6. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, शुरुआत में, रक्षा खरीद से संबंधित सरकारी निर्णयों की न्यायिक जांच के मानदंडों को निर्धारित करना और यह इंगित करना उचित होगा कि क्या ऐसे मानदंड निविदाओं और अनुबंधों के पुरस्कार की न्यायिक जांच के न्यायशास्त्र की तुलना में अधिक संकुचित हैं, जो आज तक सामने आया है, वैध रूप से अनुमति देगा।

7. निविदाओं और अनुबंधों के वितरण के संबंध में प्रशासनिक निर्णयों की न्यायिक समीक्षा के मानदंड वास्तव में वाणिज्यिक और आर्थिक गतिविधियों में राज्य

की बढ़ती भागीदारी से विकसित हुए हैं। जगदीश मंडल बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य में यह न्यायालय, सचेत वाणिज्यिक लेन-देन में सीमाओं के कारण, इसकी जांच निर्णय लेने की प्रक्रिया और अनुचितता और दुर्भावना के मापदंडों तक सीमित रही। वास्तव में, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करने के लिए नहीं था, भले ही एक प्रक्रियात्मक त्रुटि निविदाकार के पूर्वाग्रह के लिए प्रतिबद्ध हो क्योंकि इस तरह की न्यायिक समीक्षा का प्रयोग करते समय निजी हितों की रक्षा नहीं की जा सकती है। अनुबंध का अधिनिर्णय, अनिवार्य रूप से एक वाणिज्यिक लेनदेन होने के कारण, ऐसे वाणिज्यिक निर्णयों के लिए प्रासंगिक विचारों के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए, और इसका तात्पर्य यह है कि जिन शर्तों के अधीन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं, वे न्यायिक जांच के लिए तब तक खुली नहीं हैं जब तक कि यह नहीं पाया जाता है कि वे किसी विशेष निविदाकार या निविदाकारों के एक वर्ग को लाभान्वित करने के लिए तैयार की गई हैं। [माँ बिंदा एक्सप्रेस वाहक और ए. एन. आर. बनाम उत्तर-पूर्व सीमांत रेलवे और अन्य को देखें]

8. टाटा सेल्युलर बनाम भारत संघ से शुरू होने वाली विभिन्न न्यायिक घोषणाएं, सभी इस पहलू पर जोर देती हैं कि जांच तर्कसंगतता के वेडनसबरी सिद्धांत और दुर्भावना या पक्षपात के अभाव तक सीमित होनी चाहिए।

9. हम इस मुद्दे पर निविदा को भी नहीं भूल सकते। यह निविदा सड़कों, पुलों आदि के निर्माण के लिए नहीं है। यह विमानों की खरीद के लिए एक रक्षा निविदा है। खरीद की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, जांच का पैमाना सरकार को कहीं अधिक छूट देगा। सीमेंस पब्लिक कम्युनिकेशन नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य में भी इस पहलू पर जोर दिया गया था। जिन तीन आधारों पर इस तरह की न्यायिक जांच की अनुमति है, उन्हें लगातार "अवैधता", "तर्कहीनता" और "प्रक्रियात्मक अनुचितता" माना गया है।

10. रिलायंस एयरपोर्ट डेवलपर्स (पी) लिमिटेड बनाम हवाई अड्डे भारतीय प्राधिकरण और अन्य में दो हवाई अड्डों के बीच रणनीतिक राष्ट्रीय परिसंपत्तियों के निजीकरण की नीति जांच के दायरे में आई। उक्त मामले में ग्राहम एल्डस और जॉन एल्डर द्वारा अपनी पुस्तक 'न्यायिक समीक्षा, कानून और व्यवहार के लिए आवेदन' में टिप्पणी का संदर्भ दिया गया था:

“अदालतों के अधिकार क्षेत्र को हटाने के खिलाफ एक सामान्य धारणा है, ताकि न्यायिक समीक्षा को बाहर करने वाले वैधानिक प्रावधानों को प्रतिबंधात्मक रूप से समझा जा सके। हालाँकि, सरकारी गतिविधि के कुछ क्षेत्र हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा प्रतिमान है, जिसे अदालतें खुद को जांच करने में अक्षम मानती हैं, इस प्रारंभिक निर्णय से परे कि क्या सरकार का दावा प्रामाणिक है। इस तरह के गैर-न्यायसंगत क्षेत्र में न्यायिक समीक्षा पूरी तरह से बाहर नहीं है, लेकिन बहुत सीमित है। यह भी कहा गया है कि शाही विशेषाधिकार द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ स्वाभाविक रूप से समीक्षा योग्य नहीं हैं, लेकिन सिविल सेवा संघों की परिषद बनाम सिविल सेवा मंत्री में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के भाषणों के बाद से [1985 एसी 374:(1984) 3 डब्ल्यूएलआर 1174 (एचएल): (1984) 3 ऑल ईआर 935] यह संदिग्ध है। लॉर्ड्स डिप्लॉक, स्कैमन और रोसकिली (एसआईसी) इस बात पर सहमत प्रतीत हुए कि शक्तियों के बीच कोई सामान्य अंतर नहीं है, इस आधार पर कि उनका स्रोत वैधानिक है या विशेषाधिकार है, लेकिन न्यायिक समीक्षा को किसी विशेष शक्ति के विषय-वस्तु से सीमित किया जा सकता है, उस मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा। कई विशेषाधिकार शक्तियाँ वास्तव में संवेदनशील, गैर-न्यायसंगत क्षेत्रों से संबंधित हैं, उदाहरण के लिए,

विदेशी मामले, लेकिन कुछ सिद्धांत रूप में समीक्षा योग्य हैं, जिनमें राष्ट्रीय सुरक्षा शामिल नहीं है। एक अन्य गैर-न्यायसंगत शक्ति महान्यायवादी का यह तय करने का विशेषाधिकार है कि जनहित की ओर से कानूनी कार्यवाही शुरू की जाए या नहीं।"

[जोर दिया गया]

11. यह हमारी सुविचारित राय/विचार है कि अनुबंधों, खरीद आदि के मामलों में अनुमेय न्यायिक समीक्षा की सीमा अनुबंध की विषय वस्तु के अनुसार अलग-अलग होगी और न्यायिक समीक्षा का कोई समान मानक या गहराई नहीं हो सकती है जिसे कार्य के पुरस्कार या वस्तुओं/सामग्री की खरीद के सभी मामलों में लागू होने के लिए बोर्ड सिद्धांत के रूप में समझा जा सके। इसलिए हमारे सामने आने वाली चुनौतियों की जांच राष्ट्रीय सीमाओं को ध्यान में रखते हुए करनी होगी। सुरक्षा, खरीद का विषय राष्ट्र की संप्रभुता के लिए महत्वपूर्ण है।

12. इस तरह के दृष्टिकोण को अपनाते हुए, 10 अक्टूबर, 2018 को जब पहली दो रिट याचिकाओं को शुरू में न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था, न्यायालय ने अपने आदेश में विशेष रूप से कहा था कि वह इस मामले में आगे बढ़ रहा है और भारत सरकार से न्यायालय को निर्णय लेने की प्रक्रिया में उठाए गए कदमों के विवरण से अवगत कराने की आवश्यकता है, इस तथ्य के बावजूद कि रिट याचिकाओं में कथन अपर्याप्त और कम थे। न्यायालय ने यह भी संकेत दिया था कि वह निर्णय लेने की प्रक्रिया की शुद्धता को संतुष्ट करने के लिए मामले में आगे बढ़ रहा है। यह भी स्पष्ट किया गया था कि मूल्य निर्धारण के मुद्दे या उपकरणों की तकनीकी उपयुक्तता से संबंधित मामलों पर न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा न्यायालय के समक्ष आवश्यक जानकारी को सीलबंद लिफाफे में रखने की आवश्यकता

थी। सुनवाई की अगली तारीख यानी 31 अक्टूबर, 2018 निर्धारित होने से पहले, अन्य दो रिट याचिकाएं दायर की जाने लगीं।

13. 31 अक्टूबर, 2018 को अदालत ने अपने आदेश में दर्ज किया था कि किसी भी रिट याचिका में लड़ाकू विमानों की उपयुक्तता और भारतीय वायु सेना के लिए इसकी उपयोगिता पर सवाल नहीं उठाया गया था। बल्कि याचिकाकर्ताओं को जिस बात पर संदेह था, वह है निर्णय लेने की प्रक्रिया की ईमानदारी और उस उपकरण की कीमत/लागत जिस पर इसे प्राप्त करने का प्रस्ताव किया गया था।

14. 10 अक्टूबर 2018 के आदेश के अनुसार, निर्णय लेने की प्रक्रिया में कदमों को चित्रित करते हुए सीलबंद लिफाफे में एक नोट न्यायालय को प्रस्तुत किया गया था और 31 अक्टूबर 2018 के आदेश द्वारा इस न्यायालय ने निर्देश दिया था कि ऐसी जानकारी जो न्यायालय के समक्ष रखी गई है, जिसे वैध रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में लाया जा सकता है, याचिकाकर्ताओं या उनके वकीलों को भी उपलब्ध कराई जाए। भारतीय ऑफसेट भागीदार (आईओपी) को शामिल करने के संबंध में विवरण, यदि कोई हो, का भी खुलासा किया जाना आवश्यक था। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि मूल्य निर्धारण के संबंध में विवरण; इसके लाभ, यदि कोई हों, तो सीलबंद लिफाफे में न्यायालय को प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

15. यह उपरोक्त तथ्यों और न्यायिक समीक्षा की कुछ सीमित शक्ति की पृष्ठभूमि में है जो, हमने अभिनिर्धारित किया है, वर्तमान मामले में उपलब्ध होगी कि अब हम रिट याचिकाओं में उठाए गए विवाद की जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं जो चिंता के तीन व्यापक क्षेत्रों को उठाते हैं, अर्थात्, (i) निर्णय लेने की प्रक्रिया; (ii) मूल्य निर्धारण में अंतर; और (iii) आईओपी का चयन।

निर्णय लेने की प्रक्रिया

16. 10 अक्टूबर, 2018 के आदेश के जवाब में 36 राफेल लड़ाकू विमानों के ऑर्डर देने के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में उठाए गए कदमों का विवरण दिया गया है। सरकार का कहना है कि डीपीपी 2002 के बाद 2005,2006,2008,2011,2013 और 2016 में आवधिक समीक्षा की गई है। डीपीपी की प्रस्तावना को इसके सार को पकड़ने के लिए संदर्भित किया गया है, जो इस बात पर जोर देता है कि -

“रक्षा अधिग्रहण खरीद का एक मानक खुला बाजार वाणिज्यिक रूप नहीं है और इसमें आपूर्तिकर्ता की बाधाएं, तकनीकी जटिलता, विदेशी आपूर्तिकर्ता, उच्च लागत, विदेशी मुद्रा निहितार्थ और भू-राजनीतिक प्रभाव जैसी कुछ अनूठी विशेषताएं हैं। नतीजतन, रक्षा खरीद से संबंधित निर्णय लेना अद्वितीय और जटिल बना हुआ है।”

इसमें यह भी कहा गया है कि-

"रक्षा खरीद में गर्भावस्था की लंबी अवधि शामिल होती है और खरीद में देरी से हमारे बलों की तैयारी प्रभावित होगी। सशस्त्र बलों की ज़रूरतें एक गैर-परक्राम्य और एक असम्बद्ध पहलू होने के कारण, खरीद प्रक्रिया में लचीलेपन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए भी प्रावधान किया गया है।"

कहा जाता है कि यह डीपीपी 2013 है जिसका खरीद में पालन किया गया है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि डीपीपी 2013 का अनुच्छेद 77 इस प्रकार है:

"77. यह प्रक्रिया रक्षा खरीद प्रक्रिया 2011 के स्थान पर होगी और 1 जून 2013 से प्रभावी होगी। हालाँकि, ऐसे मामले हैं जो डीपीपी-2013 की शुरुआत के समय डीपीपी के पहले के संस्करणों के प्रावधान के



अनुसार प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में होंगे। पहले की प्रक्रिया के तहत अब तक किए गए इन मामलों की प्रक्रिया को वैध माना जाएगा। केवल वे मामले जिनमें आरएफपी 1 जून, 2013 के बाद जारी किया जाता है, डीपीपी-2013 के अनुसार संसाधित किए जाएंगे।"

दूसरे शब्दों में, जब यह कहा जाता है कि केवल उन मामलों में जिनमें 1 जून 2013 के बाद आरएफपी जारी किया जाता है, डीपीपी 2013 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, इस मामले में जहां आरएफपी 1 अप्रैल 2013 से बहुत पहले जारी किया गया था और इसे वापस ले लिया गया था, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, जून 2015 में, एक प्रश्न उत्पन्न हो सकता है यह कैसे दावा किया जा सकता है कि डीपीपी 2013 का पालन किया गया था। हालाँकि, हम डीपीपी 2013 के खंड 75 पर भी ध्यान देते हैं जो इस प्रकार है:

"75. निर्धारित प्रक्रिया से किसी भी विचलन को मंजूरी के लिए डी पीपी के माध्यम से डीएसी के पास रखा जाएगा।"

17. इसके अलावा, हम देखते हैं कि आधिकारिक प्रत्यर्थीगणों ने डी पीपी 2013 के पैराग्राफ 71 से समर्थन मांगा है। आईजीए के संबंध में डी पीपी 2013 के पैरा 71 का उल्लेख किया गया है, जो मित्र देशों से खरीद की संभावनाओं को स्वीकार करता है, जो देश को प्राप्त होने वाले भू-रणनीतिक लाभों के कारण आवश्यक हैं। इस तरह की खरीद शास्त्रीय रूप से मानक खरीद प्रक्रिया या मानक अनुबंध दस्तावेज का पालन नहीं करेगी, लेकिन सक्षम वित्तीय प्राधिकरण (इसके बाद "सीएफए" के रूप में संदर्भित) से मंजूरी के बाद आईजीए के आधार पर दोनों देशों की सरकारों द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत प्रावधानों पर आधारित होगी। कुल खरीद में से लगभग 7 लाख 45 हजार करोड़ रुपये, डीपीपी के तहत 2002 से विदेशी सैन्य बिक्री और अनुबंध के मानक खंडों

सहित विभिन्न प्रकार के आईजीए का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा है। कहा जाता है कि स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2005 से एक मजबूत ऑफसेट खंड शामिल किया गया है। 2013 के रक्षा ऑफसेट दिशानिर्देशों के अनुसार, विक्रेता/मूल उपकरण निर्माता (इसके बाद "ओईएम" के रूप में संदर्भित) ऑफसेट दायित्व को लागू करने के लिए अपने आईओपी का चयन करने के लिए स्वतंत्र है।

18. जहां तक 126 लड़ाकू विमानों की खरीद के प्रयास का संबंध है, यह कहा गया है कि अन्य बातों के साथ-साथ, ओईएम और एचएएल के बीच अनसुलझे मुद्दों के कारण अनुबंध वार्ता समाप्त नहीं हो सकी। इन्हें निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

- "i) भारत में विमान के उत्पादन के लिए आवश्यक मानव-घंटे: एचएएल को भारत में राफेल विमानों के निर्माण के लिए फ्रांसीसी पक्ष की तुलना में 2.7 गुना अधिक मानव-घंटे की आवश्यकता थी।
- ii) विक्रेता के रूप में डसॉल्ट एविएशन को आरएफपी आवश्यकताओं के अनुसार 126 विमानों (18 सीधे उड़ान भरने वाले और भारत में निर्मित 108 विमान) के लिए आवश्यक संविदात्मक दायित्व निभाना आवश्यक था। भारत में निर्मित 108 विमानों के लिए संविदात्मक दायित्व और जिम्मेदारी से संबंधित मुद्दों का समाधान नहीं किया जा सका।"

19. कहा जाता है कि उपरोक्त मुद्दे तीन साल से अधिक समय से अनसुलझे हैं। कहा जाता है कि इस तरह की देरी ने अधिग्रहण की लागत को प्रभावित किया है, क्योंकि प्रस्ताव 'इन-बिल्ट एस्केलेशन' के साथ था और यूरो-रुपय विनिमय दर भिन्नताओं से प्रभावित था। गतिरोध के परिणामस्वरूप मार्च 2015 में आरएफपी वापस

लेने की प्रक्रिया शुरू की गई। इस मध्यावधि में, देश के विरोधियों ने, रक्षा मुद्दों पर, आधुनिक विमानों को शामिल किया और अपने पुराने संस्करणों को उन्नत किया। इसमें लगभग 20 स्क्वाड्रनों के 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ लड़ाकू विमानों को भी शामिल करना शामिल था, जिससे हमारे रक्षा बलों की युद्ध क्षमता प्रभावी रूप से कम हो गई। ऐसी स्थिति में, सरकार-से-सरकार की बातचीत के परिणामस्वरूप एक अलग प्रक्रिया के हिस्से के रूप में 36 राफेल विमानों की आपूर्ति के लिए आईजीए का निष्कर्ष निकला। डीपीपी 2013 के अनुसार आवश्यक कदमों का पालन किया गया है। नियम और शर्तों पर बातचीत करने के लिए एक आईएनटी का गठन किया गया था, जो मई 2015 में शुरू हुआ और अप्रैल 2016 तक जारी रहा। इस अवधि में, कुल 74 बैठकें हुईं, जिनमें 48 आंतरिक आईएनटी बैठकें और फ्रांसीसी पक्ष के साथ 26 बाहरी आईएनटी बैठकें शामिल थीं। यह आधिकारिक प्रत्यर्थीगणों का मामला है कि आईएनटी ने अपनी बातचीत पूरी की और डसॉल्ट के एमएमआरसीए प्रस्ताव की तुलना में कीमत, वितरण और रखरखाव से संबंधित बेहतर शर्तों पर पहुंचा। इसे आगे अंतर-मंत्रालयी परामर्श के लिए संसाधित किया गया और सीसीएस की मंजूरी भी प्राप्त की गई, जिसके परिणामस्वरूप समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। डीपीपी 2013 के पैरा 72 के अनुसार यह प्रक्रिया के अनुरूप था।

20. दूसरी ओर, याचिकाकर्ता आईजीए में प्रवेश करने के लिए पूर्व शर्तों की पूर्ति पर सवाल उठाना चाहते हैं। फ्रांस की सरकार, केवल 'सांत्वना पत्र' दे रही है और 'संप्रभु गारंटी' नहीं दे रही है, इस पर सवाल उठाया गया है।

21. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि पैरा 71 में तीन संभावनाओं की परिकल्पना की गई है, जहां आईजीए में प्रवेश करने का प्रश्न उत्पन्न होगा, जो वर्तमान मामले में उत्पन्न नहीं हुए हैं:

(ए) संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय अभ्यासों में भाग लेते समय हमारे सशस्त्र बलों द्वारा एक मित्र देश से संबंधित सिद्ध प्रौद्योगिकी और क्षमताओं की पहचान की जाती है;

(बी) किसी मित्र देश में सेवा में बड़ी मूल्य की हथियार प्रणाली/मंच सामान्य रूप से बहुत कम लागत पर हस्तांतरण या बिक्री के लिए उपलब्ध है; या

(ग) एक विशिष्ट अत्याधुनिक उपकरण/प्लेटफॉर्म की खरीद की आवश्यकता जहां ओईएम देश की सरकार के पास हो सकता है इसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और इस प्रकार उपकरणों का मूल्यांकन 'नो कॉस्ट नो कमिटमेंट' के आधार पर नहीं किया जा सकता है।

22. हमने सामग्री का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है। हमें वायु सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत करने का भी लाभ मिला है, जिन्होंने अधिग्रहण प्रक्रिया और मूल्य निर्धारण सहित विभिन्न पहलुओं के संबंध में अदालत के प्रश्नों का उत्तर दिया। हम संतुष्ट हैं कि प्रक्रिया पर वास्तव में संदेह करने का कोई अवसर नहीं है, और भले ही मामूली विचलन हुए हों, लेकिन इसके परिणामस्वरूप अनुबंध को रद्द नहीं किया जाएगा या न्यायालय द्वारा विस्तृत जांच की आवश्यकता नहीं होगी। हमें सूचित किया गया है कि संयुक्त अभ्यास हुए हैं और इससे हमारे राष्ट्र को वित्तीय लाभ हुआ है। यह ध्यान नहीं दिया जा सकता है कि ये रक्षा खरीद के अनुबंध हैं जो एक अलग डिग्री और न्यायिक समीक्षा की गहराई के अधीन होने चाहिए। मोटे तौर पर, प्रक्रियाओं का पालन किया गया है। विमानों की आवश्यकता पर कोई संदेह नहीं है। विमान की गुणवत्ता पर कोई सवाल नहीं है। यह भी एक तथ्य है कि 126 एमएमआरसीए की खरीद के लिए लंबी बातचीत का कोई परिणाम नहीं निकला है, और केवल यह अनुमान लगाना कि प्रारंभिक आरएफपी के परिणामस्वरूप अनुबंध हो सकता था, कोई फायदा नहीं है। कठिन तथ्य यह है कि न केवल अनुबंध सामने नहीं आ रहा

था, बल्कि बातचीत व्यावहारिक रूप से समाप्त हो गई थी, जिसके परिणामस्वरूप आरएफपी को वापस ले लिया गया था। हम 126 के स्थान पर 36 विमानों की खरीद के निर्णय के विवेक पर निर्णय नहीं ले सकते। हम संभवतः सरकार को 126 विमानों की खरीद के लिए मजबूर नहीं कर सकते। यह इस तथ्य के बावजूद है कि आरएफपी की वापसी से पहले ही अप्रैल 2015 में केवल 36 विमानों के लिए जाने के निर्णय की घोषणा की गई थी। हमारा देश ऐसी स्थिति में अप्रस्तुत/कम तैयार होने का जोखिम नहीं उठा सकता है जहां हमारे विरोधियों ने न केवल चौथी पीढ़ी, बल्कि पांचवीं पीढ़ी के विमान भी हासिल कर लिए हैं, जिनमें से हमारे पास कोई भी नहीं है। अधिग्रहण की प्रक्रिया के प्रत्येक पहलू की जांच करने के लिए एक अपीलीय प्राधिकरण के रूप में बैठना न्यायालय के लिए सही नहीं होगा।

23. हम यह भी नोट कर सकते हैं कि 36 राफेल लड़ाकू जेट विमानों के लिए प्रक्रिया 23 सितंबर, 2016 को पूरी की गई थी। तब कुछ भी सवाल नहीं उठाया गया था। यह केवल फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद के बयान का लाभ उठा रहा है कि याचिकाओं के ये समूह दायर किए गए हैं, न केवल उस पहलू के लिए जो बयान का गठन करता है, यानी आईओपी का मुद्दा, बल्कि पूरी निर्णय लेने की प्रक्रिया और मूल्य निर्धारण के संबंध में भी। हम इस मुद्दे पर आगे ध्यान देना या खंड-दर-खंड अनुपालन की मांग करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

#### कीमत निर्धारण

24. याचिकाकर्ताओं द्वारा विमानों के मूल्य निर्धारण को चुनौती इस आधार पर दी जानी चाहिए कि पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में पाई जाने वाली सार्वजनिक सामग्री के अनुसार लागत में भारी वृद्धि हुई है। हमने शुरू में मूल्य निर्धारण के मुद्दे पर भी अपनी अनिच्छा व्यक्त की थी। हालाँकि, बाद के एक आदेश द्वारा, न्यायालय की

अंतरात्मा को संतुष्ट करने के लिए, यह निर्देश दिया गया था कि विमानों की लागत के बारे में विवरण भी न्यायालय के समक्ष सीलबंद लिफाफों में रखा जाना चाहिए।

25. हमारे सामने रखी गई सामग्री से पता चलता है कि सरकार ने विमान की मूल कीमत के अलावा मूल्य विवरण का खुलासा संसद तक में इस आधार पर नहीं किया है कि मूल्य विवरण की संवेदनशीलता दोनों देशों के बीच समझौते का उल्लंघन करने के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है। हालांकि, मूल्य निर्धारण विवरण नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (इसके बाद "सीएजी" के रूप में संदर्भित) के साथ साझा किया गया है, और सीएजी की रिपोर्ट की जांच लोक लेखा समिति (इसके बाद "पीएसी" के रूप में संदर्भित) द्वारा की गई है। रिपोर्ट का केवल एक संशोधित हिस्सा संसद के समक्ष रखा गया था, और यह सार्वजनिक क्षेत्र में है। कहा जाता है कि वायु सेना प्रमुख ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले हथियारों सहित मूल्य विवरण के प्रकटीकरण के संबंध में अपनी आपत्ति व्यक्त की है। राफेल विमानों की खरीद पर भारत सरकार और फ्रांस सरकार के बीच आईजीए के अनुच्छेद 10 में मूल्य निर्धारण का विवरण शामिल किया गया है, जो यह प्रदान करता है कि आईजीए के तहत वर्गीकृत जानकारी और आदान-प्रदान की गई सामग्री की सुरक्षा दोनों सरकारों के बीच 25 जनवरी, 2008 को हस्ताक्षरित सुरक्षा समझौते के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होगी। इस अनिच्छा के बावजूद, अपनी अंतरात्मा को संतुष्ट करने के लिए सामग्री को अभी भी न्यायालय के समक्ष रखा गया है।

26. हमने मूल आरएफपी के साथ-साथ आईजीए के तहत वृद्धि लागत के साथ-साथ मूल विमान की कीमतों के विवरण और तुलना की बारीकी से जांच की है। हमने वस्तु के हिसाब से लागत पर व्याख्यात्मक टिप्पणी भी देखी है।

यह कहने के लिए पर्याप्त है कि कीमत विवरण के अनुसार, आधिकारिक प्रत्यर्थागणओं का दावा है कि 36 राफेल विमानों की खरीद में वाणिज्यिक लाभ है। आधिकारिक प्रत्यर्थागणओं ने दावा किया है कि रखरखाव और हथियार पैकेज के लिए आईजीए में कुछ बेहतर शर्तें हैं। यह है। निश्चित रूप से इस न्यायालय का काम वर्तमान जैसे मामलों में मूल्य विवरण की तुलना करना नहीं है। हम और नहीं कहते हैं क्योंकि सामग्री को गोपनीय क्षेत्र में रखा जाना है।

### ऑफसेट

27. आईओपी के मुद्दे ने इस मुकदमेबाजी को जन्म दिया है। कहा जाता है कि ऑफसेट अनुबंध डीपीपी 2013 के रक्षा ऑफसेट दिशानिर्देशों द्वारा नियंत्रित किया गया था। इनमें से दो अनुबंधों पर 23 सितंबर, 2016 को डसॉल्ट और मेसर्स एमबीडीए मिसाइल सिस्टम्स लिमिटेड के साथ हस्ताक्षर किए गए थे, उसी दिन भारत सरकार और फ्रांस सरकार के बीच आईजीए पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये क्रमशः विमान पैकेज और हथियार पैकेज के फ्रांसीसी औद्योगिक आपूर्तिकर्ता हैं। कहा जाता है कि पहले तीन वर्षों में कोई ऑफसेट दायित्व नहीं है, लेकिन ऑफसेट दायित्व अक्टूबर 2019 से शुरू होने वाले हैं।

28. याचिकाकर्ताओं की शिकायत है कि ऑफसेट दिशानिर्देशों में विचार किया गया है कि विक्रेता भारतीय ऑफसेट भागीदार के बारे में विवरण का खुलासा करेगा, हालांकि, भारत में विचाराधीन व्यावसायिक समूह की मदद करने के लिए, ऑफसेट दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 8 में एक संशोधन किया गया था, वह भी पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ। उक्त संशोधन के आधार पर यह तर्क दिया जाता है कि ऑफसेट भागीदार के बारे में गोपनीयता का आवरण डाला जाता है और विक्रेता बहुत बाद में विवरण देने में सक्षम होता है। हालाँकि, यह तर्क दिया जाता है कि ऑफसेट दिशानिर्देशों के अन्य

प्रावधान अपरिवर्तित हैं, और इसलिए, सरकार भारतीय ऑफसेट भागीदार के बारे में अज्ञानता का नाटक नहीं कर सकती है जैसा कि दायर किए गए हलफनामे में किया गया है। यह शिकायत की जाती है कि भारतीय व्यापारिक समूह का पक्ष लेने के परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध किया गया है।

29.डीपीपी 2013 के खंड 8 के अनुसार, ऑफसेट प्रस्तावों के प्रसंस्करण से संबंधित, खंड 8.2 में निम्नानुसार कहा गया है:

"8. ऑफसेट प्रस्तावों की प्रक्रिया

8.2 टीओईसी ऑफसेट दिशानिर्देशों के अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी ऑफसेट प्रस्तावों (पैरा 8.3 के अनुसार डीआरडीओ द्वारा प्रौद्योगिकी अधिग्रहण के प्रस्तावों को छोड़कर) की जांच करेगा। इस उद्देश्य के लिए, विक्रेता को ऑफसेट दिशानिर्देशों के अनुरूप अपने ऑफसेट प्रस्तावों को लाने के लिए परिवर्तन करने की सलाह दी जा सकती है। टीओईसी से अपने गठन के चार से आठ सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की उम्मीद की जाएगी।"

30. यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विक्रेता/ओईएम ने अभी तक निर्धारित तरीके से एक औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है, जो ऑफसेट निर्वहन के लिए आईओपी और उत्पादों के विवरण का संकेत देता है। 22 सितंबर, 2018 को पोस्ट की गई 'ऑफसेट नीति पर स्पष्टीकरण' के रूप में एक प्रेस विज्ञप्ति भी हमारे सामने रखी गई है। इसमें कहा गया है कि सरकार दोहराती है कि आईओपी के चयन में उसकी कोई भूमिका नहीं है। रक्षा ऑफसेट दिशानिर्देशों के अनुसार, ओईएम किसी भी भारतीय कंपनी को अपने आईओपी के रूप में चुनने के लिए स्वतंत्र है। कहा जाता है कि फरवरी 2017 में रिलायंस डिफेंस और डसॉल्ट के बीच एक संयुक्त उद्यम अस्तित्व में आया



था, जिसे दोनों निजी कंपनियों के बीच 'विशुद्ध रूप से वाणिज्यिक व्यवस्था' कहा जाता है। फरवरी 2012 की मीडिया रिपोर्टों से पता चलता है कि पिछली सरकार द्वारा 126 विमानों की खरीद के लिए सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी घोषित किए जाने के दो सप्ताह के भीतर दसॉल्ट ने रक्षा क्षेत्र में रिलायंस इंडस्ट्रीज (एक अन्य व्यावसायिक समूह) के साथ साझेदारी के लिए एक समझौता किया था। दसॉल्ट ने एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की है जिसमें कहा गया है कि उसने कई कंपनियों के साथ साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं और सौ से अधिक अन्य कंपनियों के साथ बातचीत कर रही है। दिशानिर्देशों के अनुसार, विक्रेता को या तो ऑफसेट क्रेडिट की मांग करते समय या ऑफसेट दायित्व के निर्वहन से एक साल पहले आईओपी का विवरण प्रदान करना है, जो 2020 से देय होगा। उपरोक्त प्रेस विज्ञप्ति आईओपी से संबंधित खंड के अनुरूप है जो निम्नानुसार है:

#### "4. भारतीय ऑफसेट भागीदार

4.3 ओईएम/विक्रेता/टियर-1 उप-विक्रेता ऑफसेट दायित्व को लागू करने के लिए भारतीय ऑफसेट भागीदार का चयन करने के लिए स्वतंत्र होगा बशर्ते कि आईओपी को रक्षा मंत्रालय द्वारा व्यापार करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया हो।"

31. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, उपरोक्त चित्रण के बावजूद, याचिकाकर्ता इस बात पर जोर देते रहे कि फ्रांसीसी सरकार का इस मामले में कोई कहना नहीं है। यह भी कहा गया है कि दसॉल्ट के लिए एक संयुक्त उद्यम के माध्यम से रिलायंस एयरोस्ट्रक्चर लिमिटेड की सेवाओं को शामिल करने का कोई कारण नहीं था, जब कंपनी स्वयं 24 अप्रैल, 2015 को अस्तित्व में आई थी। इस प्रकार, आरोप यह है कि भारत सरकार ने रिलायंस एयरोस्ट्रक्चर लिमिटेड को दसॉल्ट को उनके साथ अनुबंध

करने के लिए मजबूर करके लाभ दिया, और वह भी सार्वजनिक उद्यम, एचएएल की कीमत पर।

32. इसमें कोई संदेह नहीं है कि कंपनी, रिलायंस एयरोस्ट्रक्चर लिमिटेड, हाल के दिनों में अस्तित्व में आई है, लेकिन प्रेस विज्ञप्ति से पता चलता है कि संभवतः मूल रिलायंस कंपनी और डसॉल्ट के बीच वर्ष 2012 से एक व्यवस्था शुरू हुई थी। दोनों निगमों के बीच क्या बातचीत हुई, यह उनके लिए सबसे अच्छा मामला होगा, क्योंकि यह उनके वाणिज्यिक हितों का मामला है, जैसा कि वे समझते हैं। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति द्वारा दिए गए साक्षात्कार के बारे में हर तरफ से स्पष्ट इनकार किया गया है, जिसमें कहा गया है कि यह भारत सरकार है जिसने इस मामले में फ्रांस सरकार को कोई विकल्प नहीं दिया था। हमारे सामने उपलब्ध सामग्रियों के आधार पर, यह डीपीपी 2013 में आईओपी से संबंधित खंड के विपरीत प्रतीत होता है जो ऊपर निकाला गया है। इस प्रकार, हमारे विचार में, वाणिज्यिक व्यवस्था, इस स्तर पर, आईओपी की भागीदारी के संबंध में भारत सरकार को कोई भूमिका नहीं सौंपती है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह मामला डसॉल्ट के व्यावसायिक निर्णय से परे है। यही कारण है कि यह कहा गया है कि भारत सरकार की भूमिका तभी शुरू होगी जब विक्रेता/आईएम निर्धारित तरीके से एक औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा, जिसमें आईओपी और ऑफसेट निर्वहन के लिए उत्पादों का विवरण होगा। जहाँ तक एचएएल की भूमिका का संबंध है, 36 विमानों की खरीद में कोई विशिष्ट भूमिका की परिकल्पना नहीं की गई है। वास्तव में, सरकार का सुझाव ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ संविदात्मक समस्याएं थीं और डसॉल्ट एचएएल द्वारा संविदात्मक दायित्व को पूरा करने के बारे में सतर्क था, जिसे पहले के अनुबंध के गैर-समापन के लिए भी जिम्मेदार कहा जाता है।

33. एक बार फिर, यह न तो उचित है और न ही इस न्यायालय के अनुभव के भीतर इस क्षेत्र में कदम रखना जो तकनीकी रूप से संभव है या नहीं। मुद्दा यह है कि

डीपीपी 2013 में यह परिकल्पना की गई है कि विक्रेता/ओईएम अपने स्वयं के आईओपी का चयन करेगा। इस प्रक्रिया में, सरकार की भूमिका की परिकल्पना नहीं की गई है और इस प्रकार, केवल प्रेस साक्षात्कार या सुझाव इस न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा का आधार नहीं बन सकते हैं, विशेष रूप से जब दोनों पक्षों द्वारा प्रेस में दिए गए बयानों का स्पष्ट खंडन किया जाता है। हमें अभिलेख पर यह दिखाने के लिए कोई ठोस सामग्री नहीं मिलती है कि यह भारत सरकार द्वारा किसी भी पक्ष के लिए व्यावसायिक पक्षपात का मामला है, क्योंकि आई.ओ. पी. चुनने का विकल्प भारत सरकार के पास नहीं है।

निष्कर्ष:

34. तीनों पहलुओं पर हमारे निष्कर्षों को देखते हुए, और मामले को विस्तार से सुनने के बाद, हमें भारत सरकार द्वारा 36 रक्षा विमानों की खरीद के संवेदनशील मुद्दे पर इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं पाते हैं। व्यक्तियों की धारणा इस न्यायालय द्वारा विशेष रूप से ऐसे मामलों में संदिग्ध जांच का आधार नहीं हो सकती है। हम, इस प्रकार, सभी रिट याचिकाओं को खारिज करते हैं, इसे पक्षों पर छोड़ देते हैं कि वे अपना खर्च स्वयं वहन करें। हालाँकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि उपरोक्त रूप से हमारे विचार मुख्य रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के दृष्टिकोण से हैं, जिसे वर्तमान मामलों के समूह में लागू किया गया है।

निधि जैन

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक ज्योति कंवर द्वारा किया गया है ।

अस्वीकरण - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।